17 जून 2013

बारां व सिरोही में चल रही नरेगा व पेंशन योजनाओं में अनेक अनीयमिताएं

पिछले तीन सप्ताह भारत के 10 राज्यों में सरकार की पांच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सर्वेक्षण हुआ था. यह सर्वेक्षण आई आई टी दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया व विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा किया गया. जिन योजनाओं का अध्ययन हुआ, वे है - नरेगा, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, आंगनवाड़ी कार्यक्रम व मध्याहन भोजन. राजथान में यह सर्वेक्षण बारां ज़िले के किशनगंज ब्लॉक व सिरोही ज़िले के पिंडवाड़ा ब्लॉक में हुआ. किशनगंज ब्लॉक में सर्वेक्षण बासथूनी (बासथूनी ग्राम पंचायत), पगारा (बकनपुरा), दंडछत्रपुरा (रेलावन) व सिमलौद (सिमलौद) में हुआ. सिरोही में सर्वेक्षण कासीन्द्रा (अचपुरा), केर (इसरा), रीछड़ी (डुंगरी) व राजपुरा (सिवेरा) में हुआ.

दोनों ब्लोकों में नरेगा में कई अनीयामिताएं मिली. काम का बहुत आभाव था व काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं मिल रहा था. जिन लोगों को काम मिल रहा था उन्हे पूरी मज़दूरी नहीं मिल रही थी. अधिकतर मज़दूरी का भुगतान 2 - 3 महीनों की देरी से हो रहा है. हमे ये शिकायतें भी मिली कि बुज़ुर्ग लोगों को नरेगा में काम नहीं मिलता, व एक बार में परिवार के केवल एक सदस्य को काम मिलता है.

वृद्धा व विधवा पेंशन योजनाओं में सिरोही की तुलना, बारां में ज़्यादा अनीयामिताएं थी. बारां में पेंशन का भुगतान 2 - 3 महीनों की देरी से हो रहा था, और अक्सर लोगों को पूरी राशि भी नहीं मिलती है. पगारा व दंडछत्रपुरा में पेंशन राशि मनी आर्डर से घर पर आनी चाहिए, पर पगारा में लोगों को पेंशन लेने डाक घर जाना पड़ रहा था, और दंडछत्रपुरा में लोगों को डाकिए के घर. सिमलौद में लोगों को पेंशन उनके बैंक खाते में मिलती है, परन्तु उनकी पासबुक में नियमित रूप से एंट्री नहीं होती. परन्तु, यह सुनकर खुशी हुई कि पेंशन योजना में कई नए नाम जुड़ रहे थे, राज्य सरकार के आदेश के कारण.

अधिकतर बीपीएल व अन्त्योदय कार्ड धारी जिनसे बात की, उन्हे हर महीने पूरा अनाज मिल रहा था. हलाकि अप्रैल 2013 से चीनी, बीपीएल गेहूं व एपीएल आटे के दाम कम हो गए है, पर सिरोही में कुछ राशन डीलर पिछले महीने तक भी लोगों से पुराने दाम ले रहे थे. कासीन्द्रा व केर के अतिरिक्त, बाकी गाँवों में अधिकतर एपीएल कार्ड धारियों को आटा नहीं मिल रहा था. जब हमने रीछड़ी को राशन वितरण करने वाले डीलर द्वारा की गई चोरी के बारे में पिंडवाड़ा के बीडीओ को बताया, तो उन्होने आदेश दिया कि इस डीलर को हटाया जाए व जो डीलर डुंगरी पंचायत के बाकी गाँवों को राशन दे रहा है, वही अब रीछड़ी में भे वितरण करें.

दोनों ब्लोकों में आंगनवाड़ी कार्यक्रम में दिए जाने वाला पूरक पोषण आहार, बच्चों का वज़न व टीकाकरण की सेवाएं इस कार्यक्रम की बाकी सेवाओं (स्वास्थ्य व शाला पूर्व शिक्षा) से बेहतर चल रही है. पगारा में कुछ परिवार मध्याहन भोजन से संतुष्ट नहीं थे. सिमलौद में कुछ परिवारों ने कहाँ कि मध्याहन भोजन खाने के समय बंजारा व सहरिया समुदाय के बच्चे एक ओर बैठते है, व ऊंची जाति के बच्चे दूसरी ओर. अलग जाति के बच्चों को प्लेटें भी अलग अलग मिलती हैं.

हमारे पिछले तीन सप्ताहों के अनुभव से यह एक बार फिर निश्चित होता है कि ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोगों के सम्मान से जीने के लिए कितनी आवश्यक है. हम सरकारी अधिकारियों, मीडिया व अन्य समूहों से आग्रह करते है कि वे लोगों को इन योजनाओं के माध्यम से अपने मौलिक अधिकार हासिल करने में सहयोग करें.

राजस्थान की सर्वेक्षण टीम
(अमीना शेख, अंकिता अग्रवाल, गोमान, गोविन्द, इनायत सभीखी, कैलाश, महेश मेहता, मोती, मंजू, नज़र खालिद, पंकज यादव, शत्रुधन, तेयेशा मालिक)